सान्ध्य हिन्दी दैनिक　　जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 169 | जौनपुर, शुक्रवार, 15 मार्च 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

अगर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' सत्ता में आया तो यह किसानों की आवाज बनेगा - राहुल गांधी

नासिक, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया)अगर सत्ता में आता है तो वह "किसानों की आवाज" बनेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो उनकी सुरक्षा कर सकें। वह कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले के चंदवाड में एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। गांधी ने कहा, " विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की सरकार किसानों की आवाज बनेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी।" उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना के पुनर्गठन, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा करने

और कृषि को जीएसटी से बाहर करने की कोशिश करने तथा सिर्फ एक कर पर काम करने वादा किया। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने के कांग्रेस के वादे को भी दोहराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि देश में 20–25 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी देश की 70 करोड़ आबादी के पास है। उन्होंने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। गांधी ने कहा, " यह राशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 24 वर्षों के (बजट के) बराबर है जिसके तहत गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए हर साल 35 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पिछली सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। उन्होंने कहा ''अगर अमीर लोगों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। रक्षा बलों में भर्ती की 'अग्निपथ' योजना की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा।

समन के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जारी किए गए समन को सत्र अदालत में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के मामले पर सेशन कोर्ट गुरुवार (आज) को सुनवाई करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था। यह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद आया था। एक एक्स पोस्ट में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को श्परेशानश करके भाजपा में शामिल होने के लिए श्मजबूरश्शकिया जा रहा है। इससे पहले, जांच एजेंसी ने एक स्थानीय अदालत

में याचिका दायर कर दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी 2021–22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति की तैयारी को लेकर केजरीवाल के संपर्क में थे। इस मामले में अब तक जांच एजेंसी आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

संक्षिप्त खबरें

आप ने पंजाब के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा की

पंजाब, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के लिए आठ उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। उसने पांच कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा है। आप ने अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जीपी, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर, फरीदकोट से करमजीत अनमोल और बठिंडा से गुरमीत सिंह खुड्डियां को मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी आगामी आम चुनाव में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल की घोषणा विपक्ष के ए.छ.क.ए.। गुट के लिए एक बड़ा झटका है, जिसका लक्ष्य केंद्र में भाजपा को हराना है। कांग्रेस और आप विपक्ष के गुट का हिस्सा हैं।

आप और कांग्रेस पंजाब में गठबंधन करने में विफल रहे

आप और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक साझेदार हैं और उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में सीट–बंटवारे का सौदा पूरा कर लिया है। हालाँकि, वे लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत, कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि ।।च शेष 4 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन माह में जनता के विश्वास के मुताबिक काम किया – सीएम साय

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी सरकार को तीन माह हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राज्य के कलेक्टर–एसपी कांफ्रेंस में कहा कि इस अवधि में सरकार ने जनता के विश्घ्वास के मुताबिक काम किया है और मोदी की गारंटी को पूरा किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें सरकार में बैठाया है, इस तीन महीने में हमने बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बंपर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3,100 की दर से अंतर की राशि भी दे दी गई है। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किस्त की राशि भी जारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, ष्राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं। सभी योजनाओं को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है, कलेक्टर ध्यान रखें कि योजना का लाभ पहुंचाने में जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आपको जनसेवक मानते हैं। हम सब भी लोक सेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा है।

सरकार का एकमात्र उद्देश्य वन नेशन, नो इलेक्शन

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे जाने

के बाद आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सिर्फ 'वन नेशन, नो इलेक्शन' (एक राष्ट्र, कोई चुनाव नहीं) का है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च–स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और इंडिया, जो कि भारत है की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नासिक में कहा, ''प्रधानमंत्री का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। वह, स्पष्ट बहुमत, दो–तिहाई बहुमत, 400 सीट की मांग कर रहे हैं... वे बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं।'' रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद 'एक राष्ट्र, कोई चुनाव नहीं' है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इसका उद्देश्य धन और अन्य संसाधनों को बचाना है।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बर्बाद कर देंगे - सीएम योगी

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक मामले पर कहा कि जिन लोगों ने भी परीक्षा की शुचिता में सेंध लगाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो कहीं भी हों हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं। प्रॉपर्टी सील हो रही है। मुख्यमंत्री योगी बृहस्पतिवार को लोक सेवा आयोग के अंतर्गत चयनित 39 एसडीएम, 41 पुलिस अधीक्षकों और 16 कोषाधिकारियों व लेखाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम करती है तो परसेप्शन बदलता है। पहले भी लोग वही थे लेकिन मशीनरी को संदेह के दायरे में रखा गया था। आज मशीनरी वही है, लोग वही हैं, बस काम का तरीका बदला है। उन्होंने युवा अफसरों से कहा कि आपके पास जनता की दुआ लेने और बद्दुआ लेने का मौका होता है। ये आपको तय करना है की 35 साल क्या लेना है। बद्दुआ लेने वालों की बड़ी दुर्गति होती है। उन्हें कोई पूछता नहीं है। सचिवालय में भटकते मिलते हैं। जो बोया है वही काटा जाता है।

सिर्फ आठ महीने नौ दिन में पूरी हो गई भर्ती

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। यह प्रदेश की नई तस्वीर है। मात्र आठ महीने नौ दिन में पीसीएस की परीक्षा पूरी हो गई जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

ये पहले यूपी में सोचा भी नहीं जा सकता था। पहले दो से तीन साल लग जाते थे। परीक्षा में एक तिहाई सफलता बेटियों को मिली है। यह नियुक्ति पत्र वितरण का 28वां समारोह है। अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि अब आप की जिम्मेदारी है। विकसित यूपी को आगे बढ़ाने में अब आप का योगदान जरूरी है आपके माता–पिता को नमन।

नागरिकता संशोधन कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा – अमित शाह

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा और केंद्र देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करने के संप्रभु अधिकार से कोई समझौता नहीं करेगा। शाह की टिप्पणी सरकार द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद आई है। गृह मंत्री ने कहा कि कानून को रद्द करना असंभव है और सरकार इसके बारे में जनता के बीच जागरुकता फैलाएगी। शाह ने कहा ष्यहां तक कि इंडिया गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए बीजेपी पार्टी द्वारा लाया गया है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। हम इसके बारे में पूरे देश में जागरूकता फैलाएंगे। राष्ट्र ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले। सीएए असंवैधानिक होने की आलोचना को खारिज करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा ष्वे हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उस अनुच्छेद में दो खंड हैं। यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यहां एक स्पष्ट, उचित वर्गीकरण है। यह उन लोगों के लिए एक कानून है, जो विभाजन के कारण बने रहे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों ने भारत आने का फैसला किया। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए कि

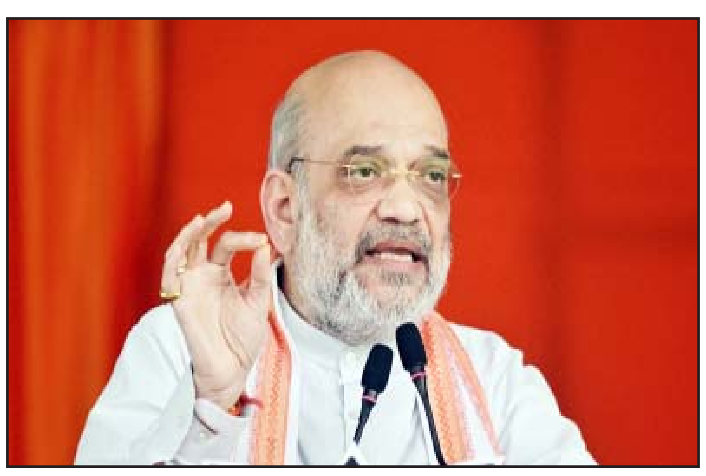

सीएए को आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है, शाह ने कहा कि कानून की अधिसूचना में ष्कोविड के कारणष देरी हुई। गृह मंत्री ने कहा "सबसे पहले मैं समय के बारे में बात करूंगा। राहुल गांधी, ममता या केजरीवाल सहित सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लिप्त हैं, इसलिए समय का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएए लाएगी और शरणार्थियों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से) को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। भाजपा का एक स्पष्ट एजेंडा है और उस वादे के तहत, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसमें कोविड के कारण देरी हुई। भाजपा ने चुनाव में जनादेश मिलने से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था। गृह मंत्री ने कहा षनियम अब औपचारिकता बन गए हैं। समय, राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है। अब, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बेनकाब हो गए हैं। सीएए किसके लिए कानून हैष पूरे देश और मैंने चार साल में लगभग 41 बार दोहराया है कि यह वास्तविकता बन जाएगी।

अमित शाह पर राजनीतिक लाभ का आरोप

गृह मंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि भाजपा का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को अधिकार और न्याय प्रदान करना है। गृह मंत्री ने कहा, विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भी सवाल उठाए थे और इसे राजनीतिक लाभ से जोड़ा था। तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेंगे। उन्होंने आगे कहा मैंने सीएए पर अलग–अलग मंचों पर कम से कम 41 बार बात की है और इस पर विस्तार से बात की है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सीएए का उद्देश्य भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। सताए गए गैर–मुस्लिम प्रवासियों – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, और इस कानून के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है।

सीएए नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं – अनुराग ठाकुर

उत्तर प्रदेश, संवाददाता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम एक ऐसा कानून है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर–मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देगा, किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए, 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादास्पद कानून को पारित किये जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर–मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर–मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, ''सीएए नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं।

पीएम मोदी ने 2 नए मेट्रो कारिडोर्स का किया शिलान्यास

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (फेज–4) के दो अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जो मोदी को गालियां देने के लिए घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। इंडी गठबंधन की विचारधारा है– कुशासन और करप्शन। मोदी की विचारधारा है– जनकल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। स्वनिधि योजना की वजह से

रेहड़ी–फुटपाथ–ठेले पर काम करने वालों की कमाई बढ़ गई है। खरीद–बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से मदद मिलने में भी आसानी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी–पटरी, ठेले और ऐसे छोटे–छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और पूजा भी है...जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था कि अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कीजिए। मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आज दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का भी शिलान्यास हुआ है।

संपादकीय

एक क्षेत्रीय मैदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी पुरस्कार लेकर भागने की धमकी दे रहे हैं। तथाकथित भारत गठबंधन का अधिकतमवादी सपना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सभी दलों का पूर्ण सीट समन्वय शामिल है, पश्चिम बंगाल में कभी भी वास्तविकता होने की संभावना नहीं थी। इस राज्य में, जहां परंपरागत रूप से भाजपा की कभी भी ज्यादा पकड़ नहीं रही है, ऐसे किसी भी चुनावी गठबंधन की कल्पना करना हमेशा असंभव था जिसमें सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और उसकी सदियों पुरानी प्रतिद्वंद्वी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) शामिल हो। फिर भी, राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्रित संकटग्रस्त उदारवादी पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा उम्मीद थी कि राहुल गांधी, एम.के. को शामिल करते हुए एक तरह की समझ बनेगी। तमिलनाडु में स्टालिन और ममता बनर्जी का आम चुनाव में प्रतीकात्मक महत्व होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी पुरस्कार लेकर भागने की धमकी दे रहे हैं। ।कअमतजपेमउमदज पिछले रविवार को, उन शानदार बड़ी सार्वजनिक बैठकों में से एक में, जिसके लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, तेजतर्रार एआईटीसी सुप्रीमो ने बहुत ही नाटकीय तरीके से भारत गठबंधन से बाहर कर दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों से एआईटीसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिनमें कांग्रेस की दो सीटें भी शामिल हैं। अपनी ओर से, कांग्रेस ने ममता बनर्जी की श्एकतरफाश घोषणा के खिलाफ कमजोर विरोध जताया, लेकिन वह इस तथ्य को छिपा नहीं सकी कि ओह–इतना चतुर गठबंधन, जिसका नामकरण बंगाली कवि–राजनेता की करतूत बताया गया था, अब कलकत्ता में लाखों गवाहों के सामने सार्वजनिक रूप से गला घोंटकर मार डाला गया। मुख्यमंत्री और उनके भतीजे का रिसता हुआ आत्मविश्वास वाजिब है या नहीं, यह चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। हालाँकि, बैठक में बनर्जी जोड़ी के भाषणों को देखते हुए, कुछ निष्कर्ष निकालना जरूरी है। सबसे पहले, बाहरी लोगों के खिलाफ बंगाल की पार्टी होने के अपने 2021 विधानसभा चुनाव के मुद्दे को पुनर्जीवित करते हुए, एआईटीसी ने यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया कि वह क्षेत्रीय स्थान पर पकड़ बनाए रखने के लिए आम चुनाव लड़ रही है। दूसरे, एआईटीसी का तीखा आग्रह कि केंद्र की मोदी सरकार ने कल्याण भुगतान में पश्चिम बंगाल में कम बदलाव किया है, विरोध की राजनीति के साथ एक था जो 1977 से 2011 तक राज्य में वामपंथी राजनीति की एक विशेषता रही थी। ममता बनर्जी का आरोप दिल्ली में औपनिवेशिक शाही शक्ति ज्योति बसु और आदरणीय भद्रलोक मार्क्सवादियों की पिछली पीढ़ियों से जुड़ी शिकायतों की एक मेलोड्रामैटिक कार्बन कॉपी थी। एआईटीसी के शीर्ष नेताओं के भाषणों को डिकोड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह अंतर्निहित दावा कि स्वामी विवेकानन्द, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय और रवीन्द्रनाथ टैगोर की कमान कालीघाट के बनर्जी परिवार पर पड़ी थी, प्रेरणादायक हो सकती है। इससे युवा बनर्जी के दावे को भी बल मिल सकता है कि 42 एआईटीसी उम्मीदवारों में से प्रत्येक बंगाल का प्रतिनिधित्व करता है, इससे कम नहीं। हालाँकि, चूंकि आगे की चुनावी लड़ाई पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण के लिए है, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि ममता बनर्जी ने काफी व्यावहारिक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि उनकी लड़ाई विपक्ष के एक छोटे से हिस्से के लिए है। यदि उन्हें विश्वास था – जैसा कि उन्होंने 2019 में किया था जब वह लोगों की शक्ति दिखाने के लिए सभी भाजपा विरोधी दिग्गजों को कलकत्ता में एक ही स्थान पर ले आई थीं – कि एआईटीसी दिल्ली में राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी का दावेदार है, तो पिछले रविवार की बयानबाजी ऐसा करेगी स्पष्ट रूप से भिन्न हो गए हैं। इसमें निश्चित रूप से श्बाहरी लोगोंश के खिलाफ आलोचना शामिल नहीं होगी। जब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो चतुर राजनेताओं का काम नवीन समाधान खोजना होता है। चुनावी राजनीति के क्षेत्र में यह चुनौतीपूर्ण है जहां लोगों को समझाना मायने रखता है। जैसे–जैसे देश आम चुनाव के करीब पहुंच रहा है, एआईटीसी नेतृत्व को इस बात का दुख है कि समग्र स्थिति भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार की संभावना के अनुकूल नहीं है। विपक्षी खेमे के रणनीतिकारों द्वारा प्रस्तुत सबसे आशावादी परिदृश्य यह है कि मोदी भाजपा की 400 सीटों की भविष्यवाणी से पीछे रह गए हैं। यह उसकी नैतिक जीत मानी जायेगी। यह विश्वास कि एनडीए साधारण बहुमत से पीछे रह जाएगा – यह 2014 में मीडिया की इच्छाधारी सोच थी – अब तक, एक संभावना के रूप में नहीं देखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सामने कठिन परिस्थिति से बेहतर तरीके से उबरने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल को मोदी की हवा से बचाने की कोशिश में, जो स्पष्ट रूप से पूरे भारत में चल रही है, वह अनिवार्य रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रही है, जिसे वह अपनी अधिक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखती है 2026 का राज्य विधानसभा चुनाव। मोदी और भाजपा के लिए, ममता बनर्जी के पंख कतरना 2024 के आम चुनाव अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले पांच वर्षों में, पश्चिम बंगाल में भाजपा एक सीमांत खिलाड़ी से आगे बढ़कर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है, जिसे राज्य के आधे से अधिक हिंदू मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। चूंकि राष्ट्रीय पार्टियां परंपरागत रूप से संसदीय चुनावों में वृद्धिशील वोट हासिल करती हैं।

दो छोटी उथल-पुथल से बड़ी लड़ाई के लिए सबक

रवि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने की अपनी कोशिश में 5 मार्च को पहली बार हार का स्वाद चखा। अमेरिका के पूर्वी तट पर बाल्टीमोर में एक प्रौद्योगिकी कंपनी के अब तक अज्ञात कर्मचारी के हाथों श्सुपर मंगलवार पर निवर्तमान राष्ट्रपति की हार काफी बुरी थी। एक निर्दयी कटौती यह थी कि अमेरिकी समोआ में डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉकस में भाग लेने वाले आधे से अधिक मतदाताओं ने विजेता जेसन पामर के स्पष्ट आह्वान का समर्थन किया कि अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है ष्जो जो बिडेन की तुलना में 21 वीं सदी का हैष। बिडेन पहले से ही व्हाइट हाउस के सबसे उम्रदराज सदस्य हैं। जब से बिडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से उनकी 81 वर्ष की बढ़ती उम्र उनके गले की फांस बनी हुई है। अमेरिकन समोआ प्रशांत महासागर में एक चित्र पोस्टकार्ड अमेरिकी श्क्षेत्रश है, जिसमें केवल 50,000 निवासी हैं। कॉकस के नतीजों के बाद, क्षेत्र अगस्त में शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में छह प्रतिनिधियों को भेजेगा, जो नवंबर चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करेंगे। कॉकस में 56 प्रतिशत वोट हासिल करने वाले पामर के सम्मेलन में तीन प्रतिनिधि होंगे। 44 प्रतिशत वोट पाने वाले बिडेन के साथ अमेरिकी समोआ के तीन प्रतिनिधि भी होंगे। उनके छोटे आकार और जनसंख्या की परवाह न करें, अमेरिकी समोआ और वर्जिन द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों से पार्टी सम्मेलनों में रंगीन और शोर–शराबे वाले प्रतिनिधिमंडलों को कोई भी नहीं भूल सकता। या उस मामले के लिए, हवाई से, जो इसके विपरीत एक पूर्ण राज्य है। ये प्रतिनिधि सम्मेलन स्थलों पर अपनी पॉलिनेशियन, पश्चिम अफ्रीकी या हिस्पैनिक संस्कृतियों और परंपराओं का प्रचार करते हुए गाते और नृत्य करते हैं। दुर्भाग्य से, अमेरिकी क्षेत्रों की राजनीतिक भागीदारी कॉकस और पार्टी सम्मेलनों के साथ समाप्त हो जाती हैरू क्षेत्रों का निर्वाचक मंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है जो नए राष्ट्रपति के चुनाव को प्रमाणित करता है। केवल राज्यों को ही यह विशेषाधिकार प्राप्त है। सुपर मंगलवार को, तथाकथित क्योंकि उस दिन 15 अमेरिकी राज्यों में प्राइमरी या कॉकस का आयोजन होता है, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प को भी इस साल के राष्ट्रपति चुनाव चक्र के शुरू होने के बाद से एकमात्र राज्य में महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। रिपब्लिकन नामांकन के लिए उनके अंतिम प्रतिद्वंद्वी, भारतीय–अमेरिकी निमाता शनिक्कीश रंधावा हेली ने अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के वर्मोंट राज्य में पार्टी प्राइमरी में जीत हासिल की। अपना अभियान स्थगित करने से पहले हेली की एकमात्र अन्य जीत कोलंबिया जिले में थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन भी शामिल है। लेकिन यह एक राज्य नहीं है, केवल एक श्जिलाश है, जो कुछ हद तक भारत के केंद्र शासित प्रदेश के समान है। कॉकस–गोअर्स और प्राथमिक मतदाताओं ने फ्रंट–रनर बिडेन और ट्रम्प को जो हार दी, उसके महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वे नवंबर के लिए हवा में उड़ने वाले तिनके

हैं, और इसलिए, इस कॉलम में एक लंबा एक्सट्रपलेशन है। वर्मोंट शायद अमेरिका का सबसे उदार राज्य है। कई मायनों में, यह वह जगह है जहां श्अमेरिकी सपनाश जीवित है, भले ही क्लासिक, एक बार अति सुंदर, सपना महाद्वीपीय अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में खट्टा हो गया है। उदाहरण के लिए, यह दो राज्यों में से केवल एक है, जहां वॉटरफ्रंट, सैरगाह और समुद्र तट जैसे सामान्य क्षेत्र सभी वर्मोंटवासियों के लाभ के लिए राज्य–शासित सार्वजनिक ट्रस्ट हैं। अमेरिका के अधिकांश हिस्सों की तरह इन्हें रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा हड़पा नहीं जा सकता। न्यू इंग्लैंड वर्तमान में दो–पक्षीय प्रणाली से दूर जाने के लिए आशा की किरण प्रदान करता है, जो कि कसकर नियंत्रित राजनीति में बदल गई है जो एक–पक्षीय शासन से बहुत अलग नहीं है और बहुलवाद के माध्यम से बहुत कम प्रदान करती है। वर्मोंट के बर्नी सैंडर्स उन तीन अमेरिकी सीनेटरों में से एक हैं जो स्वतंत्र हैं। वर्मोंट के रिपब्लिकन गवर्नर फिल स्कॉट ग्रैंड ओल्ड पार्टी (जीओपी) के क्षेत्रीय नेताओं में से एक हैं, जो अभी भी खड़े हैं, भले ही वह ट्रम्प बैंडवागन पर नहीं कूदे हैं। स्कॉट और कई रिपब्लिकन राज्य विधायकों के समर्थन ने वर्मोंट में हेली की जीत को संभव बनाया। वर्मोंट से पहले, न्यू हैम्पशायर में, हेली ट्रम्प से हार गईं, लेकिन प्राथमिक मतदाताओं के बीच सम्मानजनक शक्ति प्रदर्शन के साथ। यह एक ऐसा राज्य है जहां कुछ अन्य राज्यों के विपरीत डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन प्राइमरी में वोट देने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, जो मतदाता निर्दलीय के रूप में पंजीकृत हैं, वे भाग ले सकते हैं। न्यू हैम्पशायर के रिपब्लिकन प्राइमरी में 44 प्रतिशत मतदाताओं ने खुद को निर्दलीय के रूप में पहचाना और उनमें से लगभग 60 प्रतिशत ने हेली को वोट दिया। लगभग इतने ही प्रतिशत स्नातक मतदाताओं ने हेली का समर्थन किया। सालाना 1,00,000 डॉलर या उससे अधिक कमाने वाले अधिकांश परिवारों ने हेली को वोट दिया, जबकि इसका आधा या उससे कम कमाने वाले बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से ट्रम्प को वोट दिया। हाल की जमीनी स्तर की राजनीति में एक स्विंग राज्य, न्यू हैम्पशायर के मतदान रुझान नवंबर में ट्रम्प और बिडेन के बीच दोबारा मैच के नतीजे का संकेत दे रहे हैं।

वैश्विक जल संकट पर आमूल–चूल पुनर्विचार की आवश्यकता

ललित

इसके अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में जल संकट पैदा हो रहा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। दुनिया भर के किसान आंदोलन की राह पर हैं. यूरोप में, वे गिरती कीमतें, बढ़ती लागत, भारी विनियमन, दबंग खुदरा विक्रेताओं, ऋण और सस्ते आयात जैसे मुद्दे उठाते हैं। जलवायु परिवर्तन भी विवाद का विषय है. जबकि बाढ़ और सूखा जैसी चरम घटनाएं किसानों के लिए एक बड़ा बोझ बन गई हैं, वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा लागू किए गए पर्यावरण नियमों का भी विरोध करते हैं। भारतीय किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को खत्म करने, डब्ल्यूटीओ समझौतों से वापसी और बीज की गुणवत्ता बढ़ाने जैसी मांगें उठाते हैं। अन्य हाशिये पर पड़े समुदायों के प्रति उनकी चिंता जनजातीय समुदायों की भूमि, जंगलों और जल स्रोतों की सुरक्षा की उनकी मांग में परिलक्षित होती है। जैसा कि कहा गया है, भारत भर में तेजी से घटता भूजल भंडार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका समग्र कृषि उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जिसका उनकी मांगों में कोई उल्लेख नहीं है। कृषि उत्पादकता के लिए एक प्रमुख राज्य पंजाब का मामला लीजिए। राज्य के 138 जल ब्लॉकों में से 100 से अधिक पहले से ही अत्यधिक दोहन के गंभीर चरण में पहुँच चुके हैं – कुछ ब्लॉक भूजल दोहन से 200 प्रतिशत अधिक हैं, कुछ तो 400 प्रतिशत से भी अधिक। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद से, भूजल ने देश की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए चावल जैसी पानी की कमी वाली फसलों की सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन यह उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता पर आधारित था। भारत में भूजल की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण उपलब्धता में कमी से देश के 1.4 अरब लोगों में से एक तिहाई से अधिक की आजीविका को खतरा हो सकता है। भूजल दुनिया की लगभग आधी पेयजल जरूरतों को पूरा करता है, 40 प्रतिशत सिंचाई की जरूरतों को पूरा करता है, और बाकी का उपयोग उद्योग द्वारा किया जाता है। भूजल का एक महत्वपूर्ण कार्य जलधाराओं के आधार प्रवाह को बनाए रखना है। वैश्विक स्तर पर, कई जलभृत प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नदी बेसिन जलभृत भी शामिल हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि भूजल की अत्यधिक कमी के कारण लवणीकरण और भूमि का धंसना हुआ है। भारत सालाना 75 अरब घन मीटर भूजल निकालता है, जो वैश्विक स्तर पर खनन किए गए कुल भूजल का लगभग एक तिहाई है। नीति आयोग के अनुसार, 2020 तक 40 प्रतिशत भारतीयों के पास पीने के पानी तक पहुंच नहीं हो सकती है और चेतावनी दी गई है कि कई प्रमुख शहरों में सूखे जलभृतों का खतरा है। पिछले तीन दशकों में, भारत अनियमित जलवायु और अत्यधिक दोहन के कारण भूजल की तेजी से कमी से जूझ रहा है। अनुमान है कि पिछले 50 वर्षों में भारत में भूजल का उपयोग 10–20 घन किमी से बढ़कर 240–260 घन किमी हो गया है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज प्रयोगशाला के एक शोधकर्ता मैथ्यू रोडेल का अनुमान है कि उत्तर भारत में भूजल प्रति वर्ष 19.2 गीगाटन की दर से खध्त्म हो रहा है। उपग्रह अवलोकनों पर आधारित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर–पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्से भूजल निकासी के कारण प्रति वर्ष 1 सेमी की दर से डूब रहे हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाले एक अध्ययन में पाया गया है कि यदि उपयोग की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही, तो 2080 तक भारत में कमी की दर तीन गुना हो सकती है, जिससे भारत की खाद्य और जल सुरक्षा को और खतरा होगा। व्यापक स्तर पर, विशेषज्ञों ने जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ते मध्यम वर्ग और जलवायु परिवर्तन को पानी की कमी के प्रमुख चालकों के रूप में पहचाना है। सूक्ष्म स्तर पर, जल प्रदूषण, चोरी, रिसाव, प्रबंधन की कमी और उपेक्षा समस्या को बढ़ा देती है। 2015–16 में एक प्रदर्शन ऑडिट में, 14 राज्यों ने जल प्रबंधन पर 50 प्रतिशत से नीचे स्कोर किया। ये श्कम प्रदर्शन करने वालेश उत्तर और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले कृषि क्षेत्रों और उत्तर–पूर्वी और हिमालयी राज्यों में केंद्रित हैं। कई हिस्सों में भूजल का प्रदूषण भी चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2018 में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। ओडिशा, बंगाल, राजस्थान और गुजरात के हिस्से भूगर्भिक और मानवजनित प्रदूषण दोनों से प्रभावित हैं। स्थिति और खराब होने की आशंका है क्योंकि ग्रामीण आबादी को अपनी कृषि भूमि से कम उत्पादकता और आय का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शहरों की ओर पलायन हो रहा है और शहरी स्थानों में भीड़भाड़ हो रही है, जो पानी की पर्याप्त उपलब्धता से भी जूझ रहे हैं। शहरी आबादी में वृद्धि ने संसाधन आधार पर दबाव बढ़ा दिया है। 2018 और 2050 के बीच शहरी आबादी में अनुमानित वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। जमीनी अध्ययन से यह भी पता चलता है कि नदियों की निचली पहुंच में लवणता और नाइट्रेट संदूषक बढ़े हुए हैं। राजस्थान में कुओं से एकत्र किए गए पानी के नमूनों के अध्ययन से फ्लोराइड, नाइट्रेट और यूरेनियम के व्यापक प्रदूषण का पता चलता है। बंगाल में आर्सेनिक विषाक्तता नदी बेसिन गंभीर हो गई है।

तख्तापलट और गृह युद्ध के 3 साल

आदित्य

1 फरवरी 2021 को, म्यांमार के सशस्त्र बलों (टाटमाडॉ) ने 2020 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की भारी चुनावी जीत को खारिज कर दिया और सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 2020 के चुनावों में व्यापक धोखाधड़ी के आरोप ने एक संकट पैदा कर दिया, जिसमें सेना ने, अपने द्वारा लिखे गए संविधान के परिणाम स्वरूप सरकार पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हुए, चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तख्तापलट ने व्यापक सविनय अवज्ञा, विरोध और सशस्त्र प्रतिरोध को उकसाया।

गृह युद्ध

2021 तख्तापलट के बाद, विपक्षी कार्यकर्ताओं और पूर्व सांसदों ने एक छाया सरकार बनाई, जिसे राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) के रूप में जाना जाता है। एनयूजी प्रतिरोध जुटाने और स्थानीय मिलिशिया के कार्यों का समन्वय करने के लिए काम कर रहा है, जिन्हें पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (पीडीएफ) के रूप में जाना जाता है। पीडीएफ तीन प्रकार के सशस्त्र समूहों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो तख्तापलट के बाद उभरे हैं– पीडीएफय स्थानीय रक्षा बल (एलडीएफ), और पीपुल्स डिफेंस टीम (पीडीटी)। पीडीएफ एनयूजी द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त बड़ी सशस्त्र इकाइयाँ हैं, जो कई जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ संयुक्त कमांड सिस्टम के तहत काम करती हैं। जून 2019 में, तीन सशस्त्र समूहों– अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और ताश्आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने द थ्री ब्रदरहुड अलायंस नामक एक गठबंधन बनाया। 2 बर्मी जुंटा का विरोध करने में गठबंधन 2023 में प्रमुखता से उभरा। 27 अक्टूबर 2023 को, गठबंधन ने ऑपरेशन 1027 शुरू किया, जो उत्तरी शान राज्य में जुंटा के खिलाफ एक आक्रामक अभियान था। गठबंधन और अन्य प्रतिरोध ताकतें अब तक देश के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं। गृहयुद्ध ने गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि अब 2.6 मिलियन से अधिक लोग म्यांमार के भीतर विस्थापित हो गए हैं, इनमें से लगभग 800,000 विस्थापन अक्टूबर 2023 के अंत से हुए हैं। भारत में, म्यांमार के उत्तर–पश्चिम क्षेत्र के लगभग 59,200 व्यक्तियों ने फरवरी 2021 से सुरक्षा की मांग की है। इनमें से, लगभग 5,500 नई दिल्ली में हैं और यूएनएचसीआर के साथ पंजीकृत हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि श्म्यांमार में सुरक्षा बलों ने तख्तापलट के एक साल के भीतर कम से कम 1,600 लोगों की मौत का कारण बना है और 12,500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य तख्तापलट के बाद शुरुआती 20 महीने की अवधि के दौरान कम से कम 6,000 नागरिक मारे गए। द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट (एसीएलईडी) के अनुसार, 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से, देश में कम से कम 50,000 लोगों की अनुमानित मृत्यु देखी गई है, जिसमें कम से कम 8,000 नागरिक शामिल हैं।

जुंटा की कमजोर स्थिति

ऑपरेशन 1027 में जुंटा के हवाई हमलों में वृद्धि देखी गई है, जिससे अक्टूबर 2023 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा दर्ज 554 से अधिक मौतों के साथ महत्वपूर्ण नागरिक हताहत हुए हैं। सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए नागरिकों की कुल संख्या 1,600 से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष में लगभग 300 से तेज वृद्धि दर्शाती है। 12 नवंबर 2023 में, कारेनी जातीय सशस्त्र संगठनों (ईएओ) के एक गठबंधन ने काया (कारेनी) राज्य में ऑपरेशन 1111 नाम से एक स्वतंत्र आक्रामक अभियान शुरू किया। इसके साथ ही, अराकान आर्मी (एए) ने, स्पष्ट रूप से ताश्आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) और कारेनी बलों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, राखीन राज्य में कई सैन्य चौकियों पर हमले शुरू किए, जिससे तुलनीय सफलता प्राप्त हुई। 13 इसके अलावा, तातमाडॉ चल रहे हमलों का मुकाबला करता है चिन, काचिन और मोन राज्यों में, विभिन्न पीडीएफ के रूप में, अपदस्थ सरकार द्वारा स्थापित एनयूजी के सशस्त्र गुटों का प्रतिनिधित्व करते हुए, दक्षिणी ब्रदर्स आर्मी की स्थापना करके तनिनथारी क्षेत्र में काम करते हैं। 14 राज्य प्रशासन परिषद (एसएसी) ने प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले केंद्रीय गलियारे को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण खो दिया है। विद्रोही समूहों का अब अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा है, जिसमें सात संपूर्ण राज्य और पांच अन्य के हिस्से शामिल हैं। वे पड़ोसी देशों की ओर जाने वाली कुछ प्रमुख सड़कों को भी नियंत्रित करते हैं।

भारतीय नौसेना के कमांड, नियंत्रण के पुनर्गठन का समय

आसिफ

क्या भारत यूरोप और लेवांत के भूमि युद्धों में नौसैनिक बलों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दे रहा है? या चीनी नौसैनिक आक्रामकता में अभूतपूर्व वृद्धि, जो दक्षिण एशिया के समुद्र तट के आसपास के समुद्र में लगातार किसी को भी शिकार बना रही है? क्या भारत भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उसके आसपास तथा नई दिल्ली के 4,104 समुद्री मील समुद्र तट से सटे द्वीपों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नौसेना के शत्रुतापूर्ण कृत्यों की आंच महसूस नहीं कर रहा है? यह भारत की स्थापना के लिए आपातकाल जैसी स्थिति को पहचानने का समय है जिसके लिए अपने क्षेत्र में नौसेना बलों की कमान, नियंत्रण और आगे की तैनाती के पुनर्गठन की आवश्यकता है। भारत जैसी कोई अन्य गैर–पश्चिमी नौसेना नहीं है जिसे शांतिपूर्वक तैनात किया जा सके या कम से कम 20 हिंद महासागर तटीय राज्यों की मदद करने के लिए योग्य हो, जिस तरह से भारत के नाविक बाब अल मंडेब, अरब सागर और लाल सागर के पानी में काम कर रहे हैं। मध्य पूर्व में, जबकि भारत के यहूदी राज्य के साथ अच्छे संबंध हैं और अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ–साथ खाड़ी अमीरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनमें से सभी में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, लाल सागर में हौथी विद्रोहियों का अनियमित व्यवहार और हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूह अप्रत्याशितता कारक लाते हैं, भले ही उनके पास भारत या इसकी पेशेवर नौसेना के साथ कोई गंभीर समस्या न हो। सबसे बड़ा अज्ञात कारक जो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्गों को प्रभावित कर सकता है, वह पीएलए नौसेना की गतिविधियां हैं – क्या इसे दक्षिण चीन सागर के आसपास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक अपने दबंग आचरण का विस्तार करना चाहिए। भारत के लिए भू–राजनीतिक परिदृश्य वास्तव में अधिक जटिल होता जा रहा है, पारंपरिक भूमि और क्षेत्रीय मुद्दे दूरगामी परिणामों के साथ पानी पर फैल रहे हैं। नवीनतम गंभीर उकसावे मालदीव के अस्थिर, अनियमित और गुमराह प्रतिष्ठान से उत्पन्न हुए हैं। अपने सामरिक महत्व को प्रदर्शित करने और समुद्र में जीवन से भी बड़ी भूमिका निभाने की उत्सुकता में, इसने अनजाने में मधुमक्खी के छत्ते को हिला दिया है। चीन को स्पष्ट रूप से भारत के ईईजेड के अंदर एक इच्छुक और लचीला लिलिपुट मिल गया है। भारतीय नौसेना को अब इन जलक्षेत्रों में और अधिक मुखर होना होगा, क्योंकि वह किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर इस तरह के हथियार उठाने की इजाजत नहीं दे सकती। भारतीय नौसेना की कमान और नियंत्रण के पुनर्गठन और इसके बेड़े की तैनाती को संशोधित करने की आवश्यकता अत्यंत जरूरी हो गई है। नौसेना की तीन क्षेत्रीय कमान हैं, विशाखापत्तनम (पूर्व), मुंबई (पश्चिम) और कोच्चि (दक्षिण)। हालाँकि, प्रभावी रूप से, केवल पूर्व और पश्चिम ही परिचालन कमान हैं, जबकि दक्षिण प्रशिक्षण का प्रभारी है। इस लेखक का मानना है कि नौसेना को अपने सभी अड्डों को उन्नत करके अपने विस्तार और मजबूती के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि कोच्चि ष्प्रशिक्षण, जहाज निर्माण और रखरखाव कमानष है। विजाग और मुंबई के अलावा, लैकाडिव और मिनिकॉय को लंबी दूरी और आक्रामक जहाजों, पनडुब्बियों और एयर विंग के साथ नई दक्षिण–पश्चिम नौसेना कमान बनाया जा सकता है। अंडमान ट्राई–सर्विसेज कमांड को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कमांड बनाने के लिए इसका और विस्तार किया जाना चाहिए। पश्चिम और पूर्व के दो सीमावर्ती राज्यों – गुजरात और पश्चिम बंगाल – को स्वतंत्र परिचालन जिम्मेदारी और क्षमता के साथ दो बेड़े (हालांकि जरूरी नहीं कि तीन सितारा वाइस–एडमिरल के तहत) के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए। किसी को यह याद रखना चाहिए कि चीनी पहले ही म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तीनों पड़ोसी नौसेनाओं में काफी अंदर तक घुस चुके हैं। पनडुब्बियां, फ्रिगेट, विध्वंसक और कार्वेट सभी ढाका, नेपिटाव और इस्लामाबाद द्वारा बीजिंग से मंगाए जाते हैं, जिससे पुर्जों, रसद और रखरखाव पर बैंकिंग होती हैय सभी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति भारत के विरुद्ध अभियानों पर चीनी नौसैनिक सिद्धांत से प्रभावित हैं। सच है, भारत का लक्ष्य बांग्लादेश या म्यांमार नहीं है, लेकिन चीनी पीएलए नौसेना के जहाज इन देश के बंदरगाहों का उपयोग करते हुए खुलेआम आसपास के क्षेत्र में छिप रहे हैं। पाकिस्तान के मामले में, दिसंबर 1971 में ढाका में आत्मसमर्पण के बाद पैदा हुए इस्लामाबाद के सेना जनरलों की जन्मजात दोषपूर्ण मानसिकता और हीन भावना के कारण यह एक अलग ही खेल है।

बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के पास आज 367 समुद्री मील (ढाका) की छोटी तटरेखा वाले चार नौसैनिक अड्डे हैं।) और 567 समुद्री मील (इस्लामाबाद), मध्य–महासागर द्वीपों के साथ भारत के 4,104 समुद्री मील की तुलना में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में चीनी भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों पर चालाकी से नजर रख रहे हैं। इसके अलावा, जहां भारत की सात सेना और सात वायु सेना कमांडों को 32.88 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर निगरानी रखनी है, वहीं नौसेना को दो परिचालन कमांडों के साथ हिंद महासागर और 7,05,40,000 वर्ग किमी क्षेत्र का सर्वेक्षण और निगरानी करनी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दो अपेक्षाकृत छोटे जल निकाय।

सेक्टर मजिस्ट्रेट की कार्यशाला में एसडीएम ने सिखाए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के गुण

क्राइम ब्यूरो जौनपुर
धनंजय विश्वकर्मा

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर के ब्लॉक सभागार में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सम्पादित कराए जाने वाले लोकसभा चुनाव में तैनात हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उक्त प्रशिक्षण में डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सुपरवाइजर को उनके दायित्व से एवं कार्यों से परिचित कराया। सेक्टर मजिस्ट्रेट लोगों को बताते हुए कहा गया कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदान बूथ के क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले गांव, मोहल्ला, क्षेत्रों का विधिवत सर्वेक्षण उनके द्वारा कर लिया जाए। जिससे कि क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का चुनाव को प्रभावित करने वाला व्यक्ति या समूह मिलता है तो चुनाव से पूर्व उस पर कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके, जिससे निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा सके। साथ ही बूथ तक परिवहन का रास्ता भी देख ले, अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अवगत कराते हुए कम्युनिकेशन प्लान एवं यातायात चार्ट में यथासंभव शुद्धिकरण कर लिया जाए। बूथ का भी भ्रमण कर लिया जाए। जिस की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में भी एक चेकलिस्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दें। अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन कमियों को स–समय सही कराया जा सके। साथ ही 80 प्लस उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, महिला मतदाता एवं विप वॉटर जैसे सांसद, विधायक अध्यक्ष सदस्य गण अन्य मंत्री कारण वी किसी सम्मान से नवाजे गए विशिष्ट जन का नाम सूची से ना काट पाए तथा उनको मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए भी आग्रह कर लिया जाए साथ ही यह सुनिश्चित कर ले कि, बीएलओ एवम सुपरवाइजर व अन्य के द्वारा जो मतदाता सुचिया संबंधित क्षेत्र में पढ़ी जानी थी वह पढ़ ली गई है। उन्होंने आशा व्यक्त कीया कि आप लोग सभी पूर्ण मनोयोग से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। । उक्त ट्रेनिंग में डिप्टी कलेक्टर प्राजक्ता त्रिपाठी, तहसीलदार मछलीशहर, बीडीओ बदलापुर द्वारा भी प्रतिभाग किया गया एवम चुवाव संबंधी अपने अनुभवों को भी साझा किया।

विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता/प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिताध्प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के बच्चों को 15 मार्च 2024 को मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 गोरखनाथ पटेल तथा परियोजना कार्यालय के समग्र शिक्षा के निपुण सेल से आए आसना शुक्ल, अंकित तथा रोहित की उपस्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के 10 छात्र छात्राओं सम्मनित किया गया। प्रथम आराधया, जलालपुर को रु0 10000, अमन, खुटहन रु0 7500, अपराजिता, डोभी रु0 5000, अनन्या, मुगंराबादशाहपुर रु0 2500, रिया, महराजगंज रु0 2500, अर्पिता यादव, मुगंराबादशाहपुर रु0 2500, शिवम, केराकत रु0 2500, अंशिका, धर्मापुर रु0 2500, संजना, केराकत रु0 2500 कशिश रानी, रामनगर रु0 2500 और निपुण मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इसके बाद परियोजना के निपुण सेल से आए सदस्यों के बैठक की गई, जिसमें जनपद की डाटा एवं शिक्षक संदर्शिका आधारित शिक्षण कार्य, 100 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति, गुणवत्ता संकुल शिक्षकों बैठक, खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ साप्ताहिक बैठक, विद्यालयवार शैक्षिक प्रगति की जाय पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया हमारे टास्क फोर्स बैठक दाता आधारित, गुणवत्ता युक्त सपोर्टिव सुपरविजन, निपुण लक्ष्य एप से एसेसमेंट के विद्यालय में 70 प्रतिशत बच्चे उपस्थिति हो सायंकाल 1 घण्टे सह शैक्षिकध्अकादमिक तथा खेल कूद के कार्य कराए जा रहे जिससे बच्चों उपस्थिति में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

परियोजना के निपुण सेल से आए सभी सदस्यों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सभागार में डाटा आधारित बैठक की गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि किसी भी डाटा आधारित पेंडेंसी को एक सप्ताह में 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाय। शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति के अन्तराल को आपसी संवाद कर निरन्तरता स्थापित किया जाय। विद्यालय स्तर पर निपुण लक्ष्य एप आंकलन सप्ताह वार किया जाय, जो बच्चे निपुण नही हो उन्हें कैसे निपुण किया जाय पर गुणवत्ता युक्त उपचारात्मक शिक्षण कर निपुण किया जाय पर बल दिया जाय। अब सत्र 2024–25 जो स्कूल के प्रधानाध्यापक बताएंगे उन्ही विद्यालयों का निपुण लक्ष्य एप से एसेसमेंट किया जाएगा। सप्ताहवार खण्ड शिक्षा अधिकारी और एआरपी की बैठक डाटा ली जाय और अगली रणनीति तय कर विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया जाय।

इकाई - फैशन और लाइफ स्टाइल प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन

मुख्य अतिथि पूजा प्रसाद, मुख्य शैक्षणिक सलाहकार, श्री राम ग्लोबल स्कूल ने किया उद्घाटन

एक छत के नीचे मिल रहे सारे उत्पाद

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। गुरुवार को राजधानी के गोमती नगर स्थित होटल हयात रीजेंसी में श्इकाईरू फैशन एवं लाइफस्टाइलश प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूजा प्रसाद, मुख्य शैक्षणिक सलाहकार, श्री राम ग्लोबल स्कूल, लखनऊ ने किया। उन्होंने इस प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए बताया कि यहां एक छत के नीचे सारे तरह के सामान उपलब्ध हैं। त्योहारों के मद्देनजर ये प्रदर्शनी अद्भुत है। क्योंकि, इकाई में पूजा की थाल से लेकर मूर्तियां, होम डेकोर और डिजाइनर कपड़ों के साथ सभी तरह के सामान हैं।

50 से ज्यादा लगे स्टॉल

प्रख्यात फैशन डिजाइनर पहली बार लखनऊ में आ रहे हैं। ऑल्टरनेटिव , वीरा वीर, आजू क्लॉथिंग, श्रेयस जैन, चांद बारी, किआशा, और बहुत सारे ब्रांड्स , सूट्स, साड़ी , ड्रेसेज, टॉप्स, ने अपना ब्रांड्स प्रदर्शित किया। ट्रेंडी फुटवियर, एक्सेसरीज , एंड ज्वैलरी बाई बॉटम लाइन शूज, हाउस ऑफ कोशा।

त्योहारों के लिए बेहद अहम है प्रदर्शनी

एक दिवसीय प्रदर्शनी के आयोजन करने वाली डिजाइनर व उद्यमी रोमा अग्रवाल, आयुषी अग्रवाल और राधिका अग्रवाल ने बताया कि हम लखनऊ की जनता के बेहद शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने हमारी प्रदर्शनी में आकर इसमें चार चांद लगा दिए। यहां वो सारे उत्पाद उपलब्ध हैं, जो आम आदमी खरीदता है।

रमजान में इबादत की आदत डाले लोग – जावेद अहमद इमाम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। इस्लामिक पवित्र महीने के पहले जुमे की नमाज शहर भर में लाखों मुसलमानों ने विभिन्न मस्जिदों में अदा की।इस मौके पर ऐतिहासिक शाही अटाला मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने नमाज अदा की ,पुलिस लाइन जामा मस्जिद में खेताब करते हुए इमाम जावेद अहमद ने कहा कि रमजान में लोग इबादत की आदत डालें उसके बाद साल भर वैसे ही इबादत करें जिस तरीके से सारे काम में से वक्त निकाल कर रमजान में लोग इबादत करते हैं ,वही इमाम ए शाही अटाला मस्जिद मौलाना सलाहुद्दीन ने नमाज ए जुमा अदा कराई,

शाही बड़ी मस्जिद मे मौलाना अबू हुरैरा ने जुमे की नमाज अदा कराई उसके पहले उन्होंने बताया की रोजेदारों को चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों में उन लोगों का भी ख्याल रखे जो कि गरीबी की वजह से रमजान में परेशान नजर आते है। शाही पुल स्थित शेर मस्जिद के कारी इश्तेयाक जिया ने नमाज अदा कराई ,खानकाह रशिदिया मीरमस्त मे मौलाना मेराज ने नमाज अदा कराई , मदीना मस्जिद नवाब साहब का हाता मे मौलाना अहमद रजा जाफरी ने नमाज अदा कराई, हादी रजा मस्जिद पॉलिटेक्निक चौराहे पर कारी आफाक ने तो वही जामा मस्जिद अहमद खां मंडी में हाफिज अब्दुल हक ने नमाज अदा कराई इस मौके पर मुख्य रूप से नियाज खा,इकबाल खा,आले खा,शकील खा,निजामुल हक,जियाउल हक, मंजर अंसारी,इत्यादि लोग मौजूद रहे,मरकजी सीरत कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हफीज शाह ने कहा की सभी मस्जिदों मे अकिदत के साथ जुमे की नमाज अदा की गयी और प्रशाशन व नगर पालिका का पूरा सहयोग रहा।

शाही ईदगाह कमेटी के प्रवक्ता रियाजुल हकध खान ने बताया की आज पवित्र रमजान के पहले जुमे की नमाज के मौके पर लाखों मुसलमान विभिन्न अलग अलग मस्जिदों में इक्ट्ठे हुए जहां पर नमाज के बाद दुनिया व हिंदुस्तान में अमन सुकून की दुआ मांगी गई,इसके अलावा शहर की शाही किला मस्जिद,लाल मस्जिद ,शाही लाल दरवाजा मस्जिद,आलम मस्जिद, सब्जी मण्डी मस्जिद,आया मस्जिद, आलम मस्जिद,जकरिया मस्जिद, गौशाला मस्जिद,मोहम्मद हसन मस्जिद, चहारसु मस्जिद, जहांगीरा बाद मस्जिद, शाही जुमा मस्जिद वाजिदपुर,नूर मस्जिद अहमद खा मंडी समेत सभी जुमा मस्जिदों मे जुमा की नमाज अदा शांतिपूर्वक अदा की गयी ,मौके पर प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे।

अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति एवं अन्य पिछड़ें वर्ग हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण

जौनपुर। जिला सेवायोजन कार्यालय जौनपुर द्वारा अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ें वर्ग के अभ्यर्थियों को लिपिकीय स्तरीय प्रतियोगिता सम्बन्धित एक वर्षीय ‘कार्यालय प्रबन्ध’ का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट है, अर्ह अभ्यर्थियों की आयुसीमा 01 अप्रैल 2024 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए ।

प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित विषयः– सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य गणित, सचिवीय पद्वति, बुक कीपिंग एण्ड ऐकाउन्टेन्सी, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि (स्टेनो) तथा कम्प्यूटर शिक्षा प्रमुख हैं।

उक्त वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र 19 मार्च 2024 तक जमा किया जा सकता है। अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति का साक्षात्कार 20 मार्च 2024 को तथा अन्य पिछड़े वर्ग का साक्षात्कार 21 मार्च 2024 को प्रातः 10 बजे से जिला सेवायोजन कार्यालय, जौनपुर में होगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त जानकारी हेतु अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवायोजन कार्यालय, जौनपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

‘महिलाओं के कल्याण को चलाई जा रही योजनाओं का उठाए लाभ’

’ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

’शाहजहांपुर’ जिला प्रोबेशन अधिकारी गौरव मिश्रा के निर्देशानुसर विकास खंड तिलहर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक की गई। जिसमें प्रभारी जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित द्वारा महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल सेवा योजना, वृद्धा पेंशन योजना दिव्यांग पेंशन योजना प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वन स्टाप सेंटर, आदि की जानकारी दी गई साथ ही टोल फ्री नंबर 1098, 181, 112 108, आदि टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी।

स्वास्थ्य विभाग से काउंसलर नंदिनी सक्सेना ने कहा कि आज हर जगह महिलाएं सशक्त हो रही है। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर, तंबाकू सेवन से होने वाले रोगों से बचाव व मानसिक बीमारी पर प्रकाश डाला और ध्रुमपान न करने की अपील की। कार्यक्रम में सैयद अली, राहुल स्वयं सहायता समूह से मीनाक्षी ,रीता आदि मौजूद रहे।

ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण हम सभी का नैतिक कर्तव्य - डा. कायनात काजी

प्रतिभागियों ने ऐतिहासिक स्थलों की फोटोग्राफी को सीखा पांच दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन

जौनपुर। कल्चरल क्लब एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग की ओर से पांच दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। शाही किले में ऐतिहासिक स्थलों की फोटोग्राफी विषय पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात यात्रा लेखिका एवं फोटोग्राफर डॉ. कायनात काजी ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों के चित्र सभी को आकर्षित करते हैं इसलिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां से सबसे सुंदर दिखाई देता हो। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना समाज के हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। उस स्थान को गंदा कर हम अपनी विरासत को क्षतिग्रस्त और धूमिल करते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी उसको उस रूप में नहीं देख पाएगी जिसे हमारे पूर्वजों ने दिया है।

वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार एवं फोटोग्राफर अनिरूद्ध पांडे ने उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने विडियो और फोटो के माध्यम से लोक कलाओं के संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण को विस्तार से बताया। उन्होंने चुनार, गोरखपुर एवं आजमगढ़ की लोक कलाओं पर कहा कि वह कला जीवित रहती है जिसका जुड़ाव आमजन से होता है। उन्होंने बांसुरी पर बनाई गयी वृत्तचित्र नरकट की रानी को दिखाया। प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटकर प्रख्यात फोटोग्राफर डॉ. कायनात काजी, प्रेस फोटोग्राफर आशीष श्रीवास्तव एवं हसन आरिफ जाफरी द्वारा फोटोग्राफी की तकनीक बताई गयी। प्रतिभागियों ने शाही किले की शानदार फोटो अपने मोबाइल और कैमरा में कैद की। विशेषज्ञों को कार्यक्रम समन्वयक प्रो. मनोज मिश्र द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।समापन सत्र संकाय भवन के कांफ्रेंस हाल में आयोजित हुआ। अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनील कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ. अवध बिहारी सिंह, डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव, डॉ. चंदन सिंह, डॉ. अनु त्यागी, सुधाकर शुक्ल, सोनम विश्वकर्मा समेत राज कॉलेज, मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज एवं परिसर के विद्यार्थी उपस्थित रहें।

सही भोजन बेहतर जीवन की थीम पर हुआ प्रतियोगिता का आयोजन

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में स्कूल प्रबन्धन एवंध्जिला प्रशासन के सहयोग से स्कूल कालेजों से ईट राइट स्कूलध् ईट राइट कैम्पस योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत सही भोजन बेहतर जीवन की थीम पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आज ईट राइट क्रियेटीवटी चेलेंज फेज–4 के अन्तर्गत गंगा देवी इण्टर कालेज हरदोई में स्वीच, पेंटिंग, वाद–विवाद व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 14 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया । कार्यक्रम मे प्रथम स्थान पाने वाले को 1000ध–रू0, द्वितीय स्थान पाने वालें को 800ध–रू0 व तृतीय स्थान पाने वालें को 700ध–रू0 नगद पुरस्कार व प्रमाण–पत्र तथा मेंडल देकर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा–3 से 5 तक के छात्र–छात्राओं में हुई पेंटिंग प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय खड़रा की छात्रा अन्या कश्यप ने प्रथम, प्राथमिक विद्यायल रेलवेगंज के छात्र आयुष कुमार गुप्ता को द्वितीय व प्राथमिक विद्यायल रेलवेगंज के ही छात्र विशाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा–6 से 8 तक के छात्र–छात्राओं में हुई वाद–विवाद प्रतियोगिता में वेणी माधव इण्टर कालेज की छात्रा शिबू शर्मा ने प्रथम, गंगा देवी इण्टर कालेज के छात्र आर्दश कुमार ने द्वितीय, गंगा देवी इण्टर कालेज के ही छात्र वरूण कश्यप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा–9 से 10 तक के छात्र–छात्राओं में हुई स्लोगन प्रतियोगिता में वेणी माधव इण्टर कालेज की छात्रा वैशाली शुक्ला ने प्रथम, वेणी माधव इण्टर कालेज की ही छात्रा इतिका त्रिपाठी ने द्वितीय, वेणी माधव इण्टर कालेज की ही छात्रा उन्नति पंत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा–11 से 12 तक के छात्र–छात्राओं में हुई स्पीच प्रतियोगिता में वेणी माधव इण्टर कालेज की छात्रा वैष्णवी शुक्ला ने प्रथम, गंगा देवी इण्टर कालेज के छात्र वैभव शुक्ला ने द्वितीय, रफी अहमद इण्टर कालेज के छात्र आयुष कटियार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय व अन्य स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को मुख्य विकास अधिकारी ने सम्मानित किया तथा उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए तथा बच्चों से अपील की, कि आप उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो आपके स्वास्थय के लिये बेहतर हों। सहायक आयुक्त खाद्य, सतीश कुमार द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदया व अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा कहा कि सही भोजन बेहतर जीवन इस कार्यक्रम की थीम है अपने स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें एवं अपना जीवन बेहतर बनायें। कार्यक्रम का संचालन मनीष मिश्रा द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में गंगा देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिराम सिंह, रफी अहमद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत सिंह, खुशीराम, सुभाष मौर्या, अनिरुद गांगवार व अनुराधा कुशवाहा मौजूद रहे।

चोरी के नौ महीने बाद राधा व सीता की मूर्तियां बरामद

उन्नाव, संवाददाता। त्रिपुरारपुर गांव के ठाकुरद्वारा से नौ महीने पहले चोरी हुईं राधा और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां नाटकीय ढंग से पुलिस ने बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मूर्तियां पुरवा पाटन मार्ग पर लखमदेमऊ तिराहा के पास से प्लास्टिक की झोले में मूर्तियां मिली हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांव त्रिपुरारपुर में पुस्तैनी ठाकुर द्वारा मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, राधा और कृष्ण की मूर्तियां स्थापित थीं। 11जुलाई 2023 की ठाकुरद्वारे का ताला तोड़कर चोरों ने राधा और सीता की मूर्तियां चोरी कर ली थीं। ठाकुरद्वारा के संरक्षक संजय त्रिपाठी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी ने खुलासे के लिए सीओ, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया था। लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। घटना में दो विवेचक भी बदल दिए गए। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश यादव को विवेचना सौंपी थी। मंगलवार रात विवेचक राजेश यादव को मुखबिर ने सूचना दी कि चंदीगढी तिराहे के पास से बिना नंबर की काली बाइक सवार दो युवक झोले में कुछ वजनी सामान लेकर जा रहे हैं। इस पर उनका पीछा किया गया तो पुरवा पाटन मार्ग पर लखमदेमऊ तिराहे के पास बाइक सवार युवक झोला फेंककर भाग निकले।

सभी माइक्रो-इरीगेशन कम्पनियाँ एक-एक गॉव गोद लें - डॉ. हीरा लाल

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। रिवुलिस इरीगेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटर शारदा सहायक समादेश विकास प्राधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट थ्रू

माइक्रो–इरीगेशन पर एक तकनीकी कार्यशाला होटल हिल्टन गोमती नगर लखनऊ में आयोजित की गयी। कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यशाला को प्रारम्भ करते हुए डॉ योगेश बंधु स्टेट कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड बैंक द्वारा माइक्रो–इरीगेशन से सम्बंधित समस्त प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। कार्यशाला में राजीव यादव अपर आयुक्त ग्रेटर शारदा सहायक परियोजना द्वारा माइक्रो–इरीगेशन की आवयश्कता को फसल उत्पादन में अनिवार्य बताते हुए जल संरक्षण करने पर जोर दिया। डॉ हीरा लाल अध्यक्ष एवं प्रशासक ग्रेटर शारदा द्वारा लोगो से जलवायु परिवर्तन पर सोच विकसित करने और जल संरक्षण पर कार्य करने की अपील की । उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा की हमें खेत की सिंचाई नहीं बल्कि फसल की सिंचाई करनी है जिसके लिए पानी की हर एक बूंद का उपयोग करना है उन्होंने कम पानी में अधिक फसल अधिक सिंचाई पर जोर दिया। डॉ हीरा लाल ने आये हुए समस्त माइक्रो–इरीगेशन के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे एक–एक गांव को गोद ले और वहां पर माइक्रो–इरीगेशन की पद्धति को अपना कर एक मॉडल प्रस्तुत करे जिससे प्रेरित होकर अन्य गॉव के लोग भी इस पद्धति को अपना कर जल संरक्षण की दिशा में अपना प्रयास कर सके। कार्यशाला में बोलते हुए प्रोफेसर मान सिंह रिटायर्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर नई दिल्ली द्वारा ड्रिप इरीगेशन को सबसे श्रेष्ठ माइक्रो–इरीगेशन का तरीका बताया उन्होंने बताया की विगत कई दशकों के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है की ड्रिप इरीगेशन प्रणाली से सभी देसी व विदेशी साग–सब्जियों की खेती में 50: तक पानी का बचाव हुआ है तथा फसल उत्पादन में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने प्याज, लहसुन, कद्दु, भिंडी, लोभिआ, मूंगफली, मसूर के फसलों में माइक्रो–इरीगेशन का उपयोग करने का बल दिया।

प्रोफेसर रुपिंदर ओबेरॉय किरोड़ीमल कॉलेज नई दिल्ली द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया की वर्तमान में विश्व में जल संकट सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह समस्या और भी जटिल होती जा रही है। इस संकट से निजात पाने के लिए हमें नवाचार की आव्यशकता है जिसके लिए माइक्रो–इरीगेशन सबसे उत्तम पद्धति है। कार्यक्रम में रिवुलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री कौशल जायसवाल द्वारा कहा की रिवोलिस संस्था माइक्रो–इरीगेशन की दिशा में उठाये गए प्रत्येक कदम का समर्थन करती है, उन्होंने बताया की माइक्रो–इरीगेशन से हम पानी की प्रत्येक बूँद का उपयोग कर सकते है विभिन्न जिलों में कमांड डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य किये जायेंगे संस्था उसमे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

कार्यशाला में कई तकनीकी सत्र आयोजित किये गए जिसमे माइक्रो–इरीगेशन के उपयोग और उसकी उपयोगिता के सन्दर्भ में विस्तार से चर्चा की गयी। तकनीकी सत्र में रिवुलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संतोष पाटिल, लाल बहादुर जोशी, अशोक मुद्गल कर, मुनीश गंगवार प्रेजिडेंट मॉडल गांव, आर0 के0 सिंह अपर निदेशक एग्रीकल्चर तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों और माइक्रो –इरीगेशन की कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने–अपने विचार रखे गए. कार्यक्रम का समापन डॉ योगेश बंधु स्टेट कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड बैंक (ॅत्ळ –2030) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

भाजपा नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह सेनानी ने हमारा आँगन–हमारे बच्चे कार्यक्रम का किया शुभारंभ

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) जिस तरह बच्चे अपने घरों में खुलकर रहते हैं, इसी तरह स्कूलों में भी माहौल बनाया जाए। ताकि बच्चे बिना डरे पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में खुलकर भाग लें। धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी ने

हमारा आँगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करते हुए किया। ब्लाक संसाधन केंद्र भरखनी में बेसिक शिक्षा व बाल विकास पुष्टाहार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन–हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन में छात्र, संकुल शिक्षक व शिक्षक तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत भी किया गया। बीआरसी भरखनी के प्रशिक्षण हाल में मुख्य अतिथि धीरेंद्र प्रताप सिंह सेनानी डायरेक्टर गन्ना समिति, ब्राण्ड एम्बेसडर, निपुण भारत मिशन ने आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग व बेसिक शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करते हुए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आगामी सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए तैयार करना है। इससे नव प्रवेश लेते ही बच्चा स्वयं को सहज रखते हुए विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सके। खंड विकास अधिकारी अशोक द्ववेदी ने कहा बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों और परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की बाबत कहा कि आज के ये मासूम बच्चे आने वाले कल के बेहतरीन नागरिक और हमारे देश का भविष्य हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भरखनी सुनील कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उत्सव की उपादेयता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी शिक्षकों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निष्ठा पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। गीता वर्मा सुपरवाइजर आंगनबाड़ी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के पारस्परिक समन्वय से नौनिहालों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है। उन्होंने बालवाटिका स्तर पर और उसके बाद भी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने की बात कही। कही।उन्होंने तय समय सीमा पर विद्यालयों को निपुण बनाने पर जोर दिया। एआरपी सुनील कुमार, नन्हेलाल व शशि कुमार सिंह ने उपस्थित शिक्षकों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार से चर्चा की। इस अवसर सुनील कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यालय सहायक सौरभ बाजपेयी, अतुल सिंह, अंकित शुक्ल, शिखर यादव, व अनिल सिंह, की देख रेख में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सभी के प्रति आभार ब्लॉक लिपिक जैनुल्लाब्दीन ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में संजय मिश्रा, संजय त्रिवेदी, करुणेश अग्निहोत्री, अभिषेक सिंह, अजय वर्मा, द्रुपद कुमार, सचिन सिंह, राधेश्याम ठाकुर, अखिलेश सिंह, रजत बाजपेयी, पवन कुमार अग्निहोत्री, प्रशांत अग्निहोत्री, राष्मीराज अग्निहोत्री, गौरी झा, कनिष्ठा मिश्रा, मनाली पाण्डेय, सुधा देवी, रीना देवी, कंचन देवी, गीता वर्मा, जय देवी, रानी देवी, डिम्पल देवी, आदि शिक्षक, शिक्षिका व आँगनवाड़ी कार्यकत्री सहित सैकड़ों साथी उपस्थित रहे।

हरदोई की पूनम तिवारी को लखनऊ में मिला सम्मान

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर पुरुष आमंत्रण वेट लिफ्टिंग चौंपियन शिप केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में प्रदेश खेल उप निदेशक एसएस मिश्रा एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ अजय कुमार शेट्टी, रंजीत सिंह उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतोलन संघ, अरविंद कुशवाहा जिला उपकीड़ा अधिकारी लखनऊ, संजीव गोसाई राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलों के योगदान में हरदोई निवासी श्रीमती पूनम तिवारी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं कोच को शाल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ललित पटेल लक्ष्मण

अवॉर्डी और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उपस्थित रहे।

मॉडर्न,जाना बाजार बना अयोध्या का विदेशी भाषा सीखने का पहला¼फ्रेंच/जर्मन½ का केंद्र

अयोध्या। मॉडर्न ग्रुप ऑफ स्कूल,जाना बाजार की सीबीएसई ब्रांच एसडी मेमोरियल प्ले वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जाना बाजार में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6,7,8,9 के बच्चों को तीसरी भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है। जिसके लिए विद्यालय ने विदेशी संस्था , इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन लैंग्वेज, जर्मनी से संबद्धता प्राप्त कर ली है।फ्रेंच और जर्मन भाषाओं का ज्ञान भारत में कई तरह से उपयोगी हो सकता है। पहले, ये भाषाएं व्यापार, पर्यटन, और शिक्षा में उपयोगी हो सकती हैं। दूसरे, विदेशी कंपनियों या संगठनों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। तीसरे, कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी ये भाषाएं उपयोगी हो सकती हैं।यह जानकारी विद्यालय के प्रिंसिपल कौशल किशोर सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि और बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए मैनेजमेंट की पॉलिसी बहुत सराहनीय कदम बताया इसके लिए विद्यालय ने स्मार्ट क्लास की व्यस्था भी की है।

मयाबाजार उप डाकघर में बाबू की तैनाती न होने का ग्राहकों ने लगाया आरोप

अयोध्या। वर्तमान समय में मयाबाजार स्थित उप उप डाकघर बाबू विहीन चल रहा है।जिसके चलते यहां पर डाकखाने से जुड़े कामों को कराने के लिये दूर दराज से आने वाले ग्राहकों को बिना काम कराये वापस जाना पड़ रहा है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। यह आरोप इस उप डाकखाने से जुड़े ग्राहकों ने लगाते हुए बताया कि उप डाकघर पर बाबू की स्थाई तैनाती न होने के चलते वहां पर लेन देन जनवरी माह से अब अस्थाई बाबू को बीच बीच में बैठाकर कार्य किया जा रहा है।जिसके चलते इस डाकघर पर आरडी, किसान विकास पत्र, एनएससी, बचत खाते के अलावा अन्य योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है।समय से ग्राहक इस उप डाकघर में अपने पैसों का लेन–देन नहीं कर पा रहे हैं।इस संबंध में प्रवर अधीक्षक डाकघर अयोध्या मंडल एच के यादव ने बताया कि मार्च माह के अंत या फिर अप्रैल माह में मयाबाजार उप डाकघर पर स्थाई बाबू की तैनाती कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि वहां पर अस्थाई रूप से बाबू की तैनाती की जाती है।जिसके चलते इस डाकखाने पर कोई भी कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।इसके लिए वे स्वयं बीच बीच में इस डाकखाने का निरीक्षण करते हैं।

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में हुई संपन्न

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' विकास भवन सभागार में शुक्रवार को सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सीएम डैशबोर्ड पर माह फरवरी में जनपद की रैकिंग 18वीं प्राप्त हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने खराब प्रगति वाली योजनाओं के संबध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली तथा समस्त अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि अधिकारी सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय प्रगति से संबंधित आंकड़ों को समय से फीड करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने नगर निगम, एआरटीओ, रेवन्यु, विद्युत विभाग, आबकारी, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पीएम पोषण, निराश्रित गोवंश, मतस्य योजना, निराश्रित महिला पेंशन, लोक निर्माण विभाग, गन्ना विभाग, एमएसएमई सहित अन्य योजनाओं, विभागों की समीक्षा की।

अभियोजन के प्रकरणों में जघन्य अपराधों में सी श्रेणी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुये बताया कि कुछ प्रकरण विवेचना के स्तर पर लंबित है जिस कारण रैकिंग खराब है। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि पुराने प्रकरणों को अतिशीघ्र विवेचना पूर्ण कराया जाना सुनश्चित किया जाये। जिन प्रकरणों में अधिक समय से विवेचना लंबित है उनसे संबधित अभियोजकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिये। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण सही रैंक प्रदर्शित नही हो रही। जिलाधिकारी ने आयुक्त से समन्वय करके समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जल निगम की पूर्ण परियोजनाओं का जीओ टैंग कराकर निदेशक सूडा को प्रेषित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये। एडीएमएफआर को टीम गठित करके जनपद में अवैध संचरण रोकने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में सी श्रेणी प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सुधार करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित समस्त परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करें। समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन डाटा को सीएम डैशबोर्ड पर भरना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ए–प्लस रैकिंग लाने वाले अधिकारियों को सुधार करने पर सराहना भी की। जिन योजनाओं में सी,डी,ई रैंकिग है उनसे सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्ण परियोजनाए फीड करने के निर्देश दिये। बैठक में सीडीओ अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 सुरेश कमार, डीडीओ पवन कुमार सिंह, सीएमओ डॉ आरके गौतम समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

उद्योगों में बौद्धिक संपदा कितनी अहम, राष्ट्रीय आईपी यात्रा कार्यक्रम से जानें

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर (माइक्रो, स्माल, एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) एमएसएमई मंत्रालय (भारत सरकार) के सहयोग से 14 और 15 मार्च को लखनऊ के फेयरफील्ड बाय मैरिएट में राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय आईपी यात्रा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, एमएसएमई मंत्रालय, पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों और युनाइटेड ऐंड युनाइटेड के आईपीएआर विशेषज्ञ की भागीदारी कर रहे हैं। कार्यक्रम में एमएसएमई, स्टार्ट–अप क्षेत्र से और विधि और तकनीकी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित 150 से अधिक लोगों की भागीदारी रही। साथ ही पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यूपी चौप्टर की महिला उप–समिति– वीमेन इन बिजनेस अलायंस के लॉन्च की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य राज्य में महिला उद्यमियों को नेटवर्किंग, मेंटरशिप और संसाधनों तक पहुंच के लिए एक मंच देकर सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री–एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, हथकरघा, श्री राकेश सचान ने सत्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने जोर देकर इस बात का जिक्र किया कि आज माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के गतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। उन्होंने राज्य की उद्यमिता, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर केंद्रित यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के हालिया लॉन्च की भी जानकारी दी जिसके माध्यम से सूक्ष्म उद्यमियों को रू5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सचिव श्री प्रांजल यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत औद्योगीकरण के मामले में वैश्विक बाजार बन गया है और निवेश के अवसरों और व्यापारिक सहयोग के लिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। उन्होंने ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। इनके जरिए छोटे उद्यमों को उनकी क्षमता निर्माण और विकास के लिए सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में लखनऊ टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है। दरअसल, यूपी ने क्रांतिकारी कदम के तहत पहले ही टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली है। इससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार दर में वृद्धि होगी और साथ ही उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यकारी निदेशक डॉ. रणजीत मेहता ने सत्र के दौरान मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और वक्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने पीएचडी चौंबर की भूमिका के बारे में जानकारी दी जो उद्योगों, उद्यमियों और एमएसएमई को बढ़ावा देने में बढ़ावा देने के रूप में काम करता है। उन्होंने सम्मेलन का विषय भी सामने रखा। श्री वीके वर्मा, संयुक्त निदेशक और कार्यालय प्रमुख– एमएसएमई–डीएफओ कानपुर, एमएसएमई मंत्रालय (भारत सरकार) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को सभी जरूरी सहायता देने के लिए एमएसएमई–डीएफओ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की भूमिका की जानकारी दी।

उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तकनीक अपग्रेडेशन, एमएसएमई चौंपियन योजना और एमएसएमई इनोवेटिव योजना पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय की अन्य विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने मंत्रालय की प्रतिपूर्ति योजना की गाइडलाइंस के बारे में भी बताया। इतना ही नहीं उन्होंने एमएसएमई से आगे आने और पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आईपीएफसी केंद्रों से लाभ उठाने का आग्रह किया। लखनऊ सिडबी के महाप्रबंधक श्री मनीष सिन्हा ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के प्रचार, वित्तपोषण और विकास के साथ–साथ समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि सिडबी का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के क्रेडिट फ्लो को सुविधाजनक बनाने के साथ मजबूत करना और एमएसएमई ईको–सिस्टम में वित्तीय और विकासात्मक अंतराल दोनों को देखना है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. संजीव कुमार मजूमदार ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि एनआरडीसी एमएसएमई और स्टार्टअप को नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, इंक्यूबेशन तक पहुंच, फंड की पहुंच के साथ आईपीआर पर मार्गदर्शन की सुविधा देता है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि देश में इनोवेशन ईकोसिस्टम तंत्र का लाभ उठाने के लिए, एनआरडीसी ने नई दिल्ली में अपने परिसर में एक इनक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है। इसके जरिए आंत्रप्रेन्योर्स और नए स्टार्टअप्स को अपने आईडियाज पर काम करने, बिजनेस मॉडल को बेहतर बनाने और सफल उद्यम बनाने में मदद मिल रही है। श्री डीपी गोयल ने संबोधन में घरेलू और निर्यात बाजारों में एमएसएमई क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी ताकत देने के लिए आईपीआर को बढ़ावा देने की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बौद्धिक संपदा किसी भी भौतिक संपत्ति की तुलना में सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आईपी का उपयोग संसाधन जुटाने और मौद्रिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने सभी एमएसएमई को आईपी हेल्पडेस्क शिविर में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। इसके जरिए अगले दिन फाइलिंग सहायता तो मिलेगी ही साथ ही किसी भी आईपी के मामले के संबंध में उनके प्रश्नों का समाधान किया जा सकेगा।

पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उत्तर प्रदेश राज्य चौप्टर के सह–अध्यक्ष श्री राजेश निगम ने समापन टिप्पणी में कहा कि देश में आईपी ईकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग सहयोग की जरूरत है। उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस अहम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न राज्यों में आईपी को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आईपीएफसी सेंटर सेमिनार, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। श्री अतुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय निदेशक– पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तकनीकी सत्र में धन्यवाद ज्ञापन दिया। पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उत्तर प्रदेश चौप्टर की रेजिडेंट ऑफिसर सुश्री रिद्धि गर्ग ने पूरे सत्र का संचालन किया। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र हुए। इनमें युनाइटेड एंड युनाइटेड के हेड प्रोस्क्यूशन श्री वसंत चंद्रा जैसे विशेषज्ञों ने आईपीआर पर विस्तार से चर्चा की और आईपी उल्लंघन के कारण उठाए गए कुछ हालिया मुद्दों पर प्रकाश डाला। यूनाइटेड एंड यूनाइटेड के असोसिएट श्री अनमोल कक्कड़ ने आईपी रजिस्ट्रेशन और इसकी प्रक्रियाओं, पेटेंट सूचना विज्ञान, व्यावसायीकरण और तकनीकी हस्तांतरण और साथ ही आईपी से संबंधित विषयों के विस्तार पर विचार–विमर्श किया। एनएलयू, लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विकास भाटी ने भी तकनीकी सत्र को संबोधित किया और भारत में आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और उद्योग सहयोग की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला।

समीक्षा बैठक में एसडीएम ने दिए चुनाव व रमजान आदि त्योहारों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) तहसील शाहबाद में उपजिलाधिकारी शाहाबाद सुश्री पूनम भास्कर द्वारा निर्वाचन, ला एंड आर्डर, आई जी आर एस निस्तारण आदि बिन्दुओं

की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन को देखते हुए बनाये गए बूथों पर आवश्यक मूल भूत सुविधाओं का, बूथों पर साइनऐज, शौचालय, विद्युत, दिव्यांगो के लिए रैंप, आदि तथा क्रिटिकल तथा बल्नरेबल बूथों,पिछले लोकसभा मे कम वोटिंग प्रतिशत वाले बूथों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराने की प्रगति, तथा रमजान के पर्व पर जुमा के नमाजों हेतु सुरक्षा व्यवस्था आदि,तथा प्राप्त आई जी आर एस तथा समाधान दिवस के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु समीक्षा करके निर्देशित किया गया।समीक्षा बैठक में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद अनुज मिश्र, तहसीलदार शाहाबाद नरेन्द्र कुमार यादव,खंड विकास अधिकारी शाहाबाद, प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद राजदेव मिश्र,अधिशाषी अधिकारी शाहाबाद नगर पालिका शाहाबाद आर आर अंबेश उपस्थिति रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI सन्दर्भ संख्या - 24/234/2019/R/-1
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।